over the last three financial years. 1988-89 to 1990-91. As authentic information about the number of accidents and accident rates of the Armed Forces of other countries is not available, it is not possible to draw any valid comparison of the rate of accidents in the three Armed Forces of India with that in other countries.

(c) Number of military aircraft lost in accidents is as follows:

1988-90	:	34
1990-91	:	26

(e) Every accident is investigated by a Court of Inquiry and follow up action taken on the recommendations of the Court. Action on various recommendations of a high level Committee, which examined all aspects of flight safety, accepted by the Government, has been completed.

550. [*Transferred to 13th Sept.* 1991].

Selection of producers of Doordarshan Programmes

551. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any criteria for the selection of producers of Doordarshan programmes;

(b) if so, the details threof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI GIRIJA VYAS): (a) and (b) Selection and assigning of programmes to outside producers is a continuous process. The selection is made after careful examination of the theme, research of the script, professional profile and credentials of the production team and other inputs.

(c) Does not arise.

Forcible taking over of land belonging to the Schedules Castes

522. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the forcible taking over of land belonging to the Scheduled Castes in Ghaziabad by certain mafia gangs; and

(b) if so, the measures Government have taken to restore the same to the rightful owners?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) and (b) The information is being collected and shall be placed on the table of the House.

Progress in construction of T.V. tower at Rajasthan

553. SHRI B. L. PANWAR: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) what is the progress regarding the construction of R.C.C. T.V. Towers of 300 M height at border district of BARMER and JAISALMER of Rajasthan and at BUNDI;

(b) what is the anticipated cost of each project and how much amount has so far been spent on each project; and

(c) by when these projects are likely to be completed?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI GIRIJA VYAS): (a) The foundation work for the 300 M high TV tower at Jaisalmer and the 150 M high tower at Bundi has been completed and shell in respect of tower at Jaisalmer has been cast upto a height of 4.5 M. The 10 Km. approach road to he site at Barmer has been constructed and the tenders for the construction of 300 M high TV tower received.

(b) and (c) The anticipated Capital cost on the establishment of high power TV transmitter (HPT) projects at Barmer, Bundi and Jaisalmer; the expenditure incurred up to July, 91 on each of these

projects and the time-frame of their completion are given below:—

Project	Anticipated capital cost (Rs. in lakhs)	Expenditure incurred till July '91 (Rs. in lakhs)	Time-frame of completion
HPT, Barmer . .	928.75	331.56	1994-95
HPT, Bundi . . .	442.00	156·54	1992-93
HPT, Jaisalmer . .	648.25	428·38	1993-94

1991 की जनगणना के आधार पर राज्यों को आवश्यक वस्तुओं के कोटे का पुनः निर्धारण

554. **श्री राघवजी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार 1991 की जनगणना के आधार पर राज्यों को चीनी, डीजल, मिट्टी के तेल, गेहूं और तेल आदि के कोटे को पुनः निर्धारित करने जा रही है ;

(ख) यदि हां तो ऐसा पुनः निर्धारण कब तक किया जाएगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) केन्द्रीय पूल से खाद्यान्न का आवंटन राज्यों से प्राप्त मांग, केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध स्टाक, उन वस्तुओं की बाजार में उपलब्ध मात्रा तथा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परस्पर आवश्यकताओं जैसी बातों को ध्यान में रखते हुए मासिक आधार पर किया जाता है।

लेवी चीनी का आवंटन, 1-10-86 की अनुमानित आबादी के लिए प्रति महीना 425 ग्राम मात्रा उपलब्ध कराने के समान प्रतिमान के आधार पर किया जाता है । तथापि, जुलाई, 1991 में केन्द्रीय सरकार ने अगस्त, 1991 से दिसम्बर, 1991 तक लेवी चीनी के आवंटन में 5 प्रतिशत तदर्थ वृद्धि करने का निर्णय किया है । इसके बाद स्थिति की पुनरीक्षा की जाएगी ।

आयात में कमी के कारण इस समय आयातित खाद्य तेल का कोई नियमित आवंटन नहीं किया जा रहा है ।

मिट्टी के तेल का आवंटन गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि में किए गए आवंटन में उपयुक्त दर से वृद्धि करके किया जाता है । इसके आवंटन में वृद्धि मिट्टी के तेल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की उपलब्धता पर निर्भर करती है ।

केन्द्रीय पूल से किए जाने वाले सभी आवंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं और इनका प्रयोजन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की समूची आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं होता है ।

महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप

555. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप बंधन के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे,

(ख) वे लक्ष्य किस हद तक प्राप्त कर लिये गए हैं ; और

(ग) इस समय महाराष्ट्र में कितने नलकूप लगा दिये गये हैं और इनसे कितना क्षेत्र लाभान्वित हुआ है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) से (ग) लघु सिंचाई योजनाओं की आयोजना बनाने, उन्हें वित्त पोषित